ऊंची ब्याज दर के कारण पंजाब के उद्योगों में संकट

@1087. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**

श्री राम जेठमलानी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अगस्त 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पंजाब रोल्स अंडर हाई इन्टरैस्ट रेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब के उद्योग ब्याज की दर में वृद्धि हो जाने और समुचित ऋण सुविधाओं के अभाव में संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कारगर कदम उठाये है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय पंजाब में व्याप्त गड़बड़ी की स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को पंजाब में व्यापार एवं उद्योग के लिए ऋणों और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में विभिन्न रियायतें देने की सलाह दी है। इन रियायतों में मार्जिन में 10 प्रतिशत तक की कमी करना शामिल है बशर्ते कि, अधिकतम मार्जिन 15 प्रतिशत से अधिक न हो, कार्यशील पूंजी की वर्तमान सीमा में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो, अवधि को एक वर्ष तक के लिए बढ़ा कर सावधि ऋण किस्तों का पुनर्निर्धारण, बिल प्रतिधारण अवधि में एक माह की वृद्धि करना, और मांग ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/भुगतान आदेश और अन्य प्रेषणों पर वर्तमान सेवा प्रभारों में 50 प्रतिशत तक की कमी करना शामिल है। अर्थव्यवस्था में मैक्रो स्तर के असंतुलन में सुधार के लिए उपचारात्मक कदम के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ बृहत नकद ऋण सीमाओं के अन्तर्गत आहरणों पर प्रतिबंध लगा कर और उधार की दरों को बढ़ाकर कुछ ऋण नियंत्रण लागू किया है। यह ऋण नियंत्रण उपाय अस्थायी प्रकार का था और मात्र 9 मई, 1991 से 30 सितम्बर, 1991 तक की अवधि के दौरान लागू था। इसके अतिरिक्त, यह उपाय बड़े बैंक उधारकर्त्ताओं पर लागू होने योग्य था और इससे प्राथमिकता क्षेत्रों के उधारकर्त्ताओं की आवश्यकता प्रभावित नहीं हुई। ब्याज दर एक सामान्य प्रयोजन मूलक लिखत है और क्षेत्रीय आधार पर ब्याज दर में रियायत देना अपेक्षित नहीं होगा।

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 727, दिनांक 28 नवम्बर, 1991 से स्थानांतरित।

Foreign exchange earned by multinational companies

1088. SHRI DIPEN GHOSH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether under the new industrial policy Government expect foreign companies to export more than imports and be a net earner in foreign exchange;

(b) whether multinational operating in India are net earners in foreign exchange;

(c) what is the net loss of foreign exchange as per Balance Sheet of Cadburries and Colgate Palmolive;

(d) what is the value of toileteries and cream exported by Hindustan Lever and Cheesborough ponds; and

(e) what are the reasons for which these companies cannot increase exports of their products for which they are known?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Under the New Industrial Policy, payment of dividends will be monitored through the Reserve Bank of India so as to ensure that